B - IV
L - 22
Economy

दरें एवं अनुपात

(i) बैंक दर (Bank Rate):

रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से वसूली जाने वाली एकब्याज दर।

RBI द्वारा इसे प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिलों की पुनर्कटौती की दर के रूप में लागू किया जाता है।

वाणिज्यिक बिलों के द्वारा व्यापारी वर्ग वस्तु/धन का लेन देन करता है इनमें किसी विशेष राशि का भविष्य में भुगतान करने का वादा किया जाता है।

यदि इन बिलों पर कोई बैंक गारंटी दे देता है तो ये प्रथम श्रेणी के हो जाते हैं।

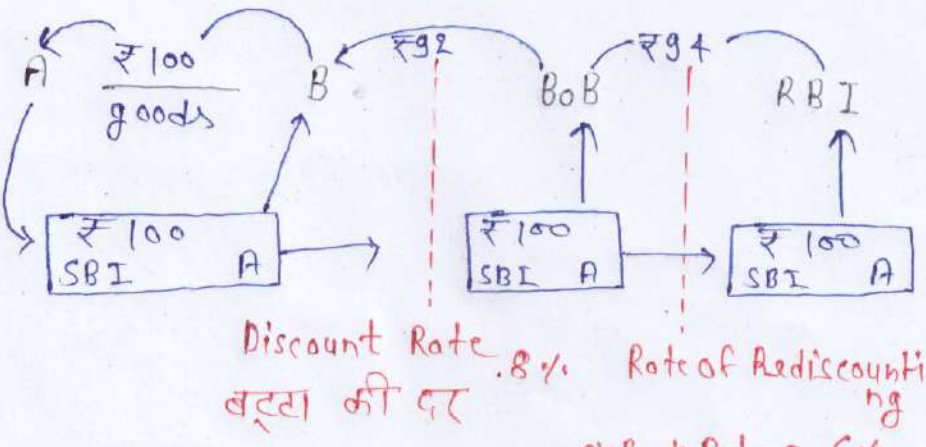

Note :-

भारत में बैंक दर अधिक प्रभावी नही है क्योंकि भारत में व्यापारी वर्ग द्वारा वाणिज्यिक बिलों का अधिक प्रयोग नही किया जाता है।

वर्ष 2011 में RBI द्वारा यह कहा गया कि MSF दर और बैंक दर एक दूसरे के बराबर रहेगी।

वर्तमान में बैंक दर 6.75% है।

रेपो दर (Repo Rate) :-

रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से वसूली जाने वाली एक ब्याजदर।

इसके आधार पर बैंक सौंपी जाने वाली G-Sec की पुनर्खरीद (Repurchase) के वादे पर रिजर्व बैंक से अति-अल्पकाल के लिए धन उधार ले सकते हैं; LTRO (Long term Repo operation) के अपवाद को छोड़ कर।

इसके अन्तर्गत बैंक निम्न समय के लिए रिजर्व बैंक से एक सीमा तक धन उधार ले सकते हैं

(i) 1- day

(ii) 3-day } ⇒ Overnight Repo

(iii) 7-day
(iv) 14-day } Term repo
(v) 28-day

इसके माध्यम से बैंक तरलता के अतिअल्पकालिक उतार-चढ़ावों का मुकाबला कर पाता है।
इसे निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है-

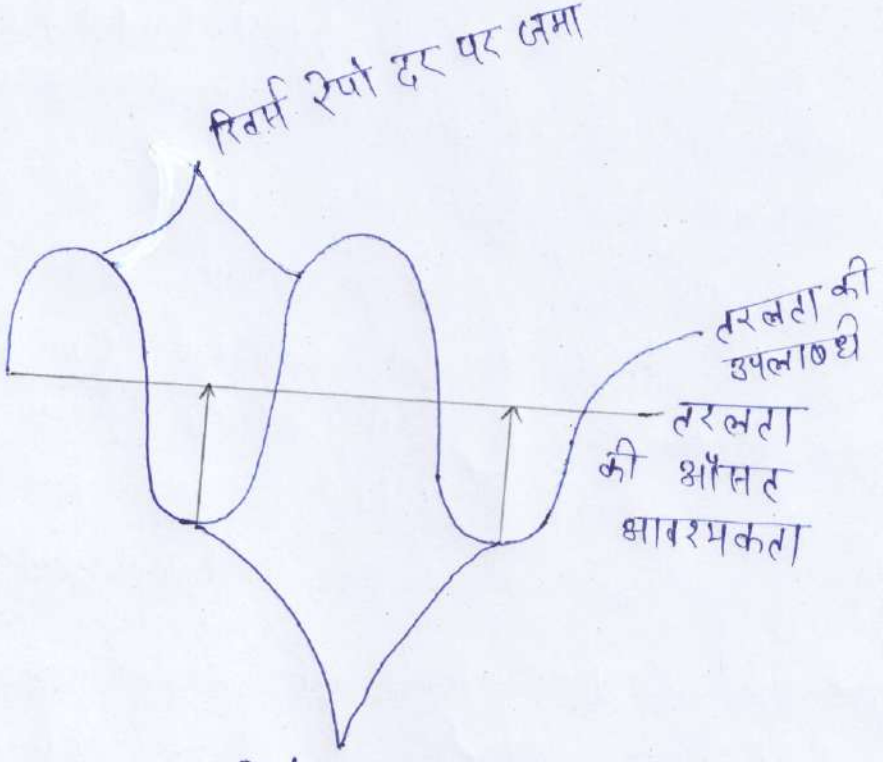

रेपो दर को Benchmark Policy rate भी कहा जाता है इसके माध्यम से Monetary Transmission Mechanism का संचालन किया जाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें ब्याज दर में परिवर्तन करके Real Sector Economy / Goods Sector Economy को प्रभावित किया जाता है

(PT- 2022)

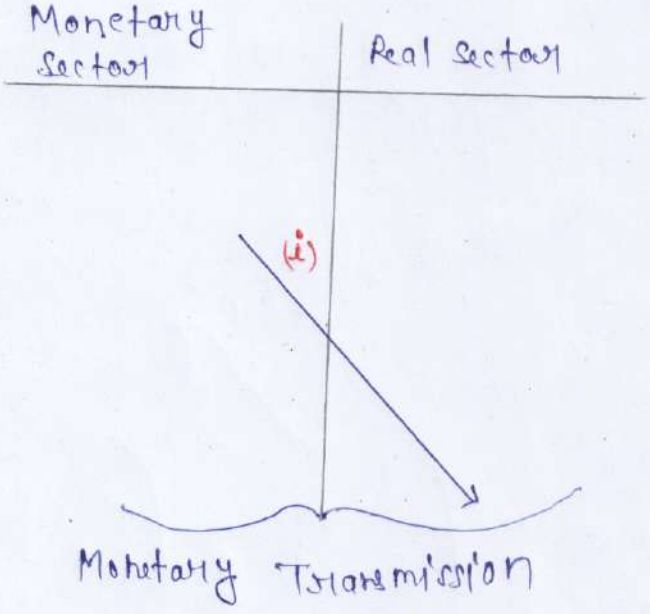

यदि रेपो दर को कम किया जाता है तो यह माना जाता है कि बैंक भी अपनी ब्याज दर कम करेंगे इससे तरलता की मांग बढ़ती है जो वस्तुगत मांग को बढ़ावा देती है वस्तुगत मांग के बढ़ने से GDP, रोजगार बढ़ते हैं

इसी प्रकार, यदि रेपो दर को बढ़ाया जाता है तो बैंक भी अपनी ब्याज दर बढ़ायेंगे। इससे तरलता की माँग कम होगी। जो वस्तुगत माँग को कम करेगी।

वस्तुगत माँग के कम होने से मुद्रास्फीति कम होगी।

1- RR↓ → Dovish या Easy / Cheaper (Monetary policy)

(ii) RR↑ → Hawkish या Tight (monetary policy)

नोट:-

वर्तमान मे RR 6.5 है।